EXAM GENIUS

Presents

WEEKLY GENIUS BANKING AND FINANCE

In BILINGUAL

19 - 25 JULY 2026

India's No. 1 Platform for UPSC | SSC | BANK RAILWAY Exam

EXAM Genius

UPSC | SSC | BANK | RAILWAY | STATE EXAMS

Ques: How many banks were live on the UPI network in June 2026?
प्रश्न: जून 2026 में UPI नेटवर्क पर कितने बैंक सक्रिय (Live) थे?

A) 675
B) 700
C) 720
D) 731
E) 750

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The number of banks live on the Unified Payments Interface (UPI) increased from 155 in June 2020 to 731 in June 2026.
• यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर सक्रिय बैंकों की संख्या जून 2020 के 155 से बढ़कर जून 2026 में 731 हो गई।
• Compared to June 2025, the number of live banks increased from 675 to 731 by June 2026.
• जून 2025 के 675 बैंकों की तुलना में जून 2026 में यह संख्या बढ़कर 731 हो गई।
• UPI added 11 new banks in June 2026 compared to May 2026.
• मई 2026 की तुलना में जून 2026 में UPI से 11 नए बैंक जुड़े।
• UPI processed 22.71 billion transactions in June 2026, registering a year-on-year growth of 23.5%.
• जून 2026 में UPI ने 22.71 अरब लेनदेन संसाधित किए, जो वर्ष-दर-वर्ष 23.5% की वृद्धि दर्शाता है।
• The increasing number of participating banks reflects the rapid expansion and adoption of India's digital payments ecosystem.
• भाग लेने वाले बैंकों की लगातार बढ़ती संख्या भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के तेज़ी से विस्तार और व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाती है।

Unified Payments Interface (UPI) | यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)

• UPI was launched in 2016 by the National Payments Corporation of India (NPCI).

• UPI की शुरुआत वर्ष 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा की गई थी।
• NPCI Headquarters: Mumbai.
• NPCI का मुख्यालय: मुंबई।

Ques: India's forex reserves increased to how much for the week ended 10 July 2026?
प्रश्न: 10 जुलाई 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया?

A) $650.16 Billion / 650.16 अरब डॉलर
B) $665.19 Billion / 665.19 अरब डॉलर
C) $675.16 Billion / 675.16 अरब डॉलर
D) $684.20 Billion / 684.20 अरब डॉलर
E) $690.10 Billion / 690.10 अरब डॉलर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• According to RBI data, India's foreign exchange reserves increased by USD 964 million to reach USD 675.16 billion for the week ended 10 July 2026.
• RBI के आंकड़ों के अनुसार, 10 जुलाई 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 964 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 675.16 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
• Foreign Currency Assets (FCA), the largest component of forex reserves, increased by USD 930 million to USD 546.51 billion.
• विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCA), जो विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, 930 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 546.51 अरब अमेरिकी डॉलर हो गईं।
• In the previous week, India's forex reserves had increased by USD 7.26 billion to USD 674.19 billion.
• इससे पहले वाले सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7.26 अरब अमेरिकी डॉलर

बढ़कर 674.19 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था।

• Foreign exchange reserves help maintain currency stability, strengthen investor confidence and protect the economy from external financial shocks.

• विदेशी मुद्रा भंडार देश की मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने तथा बाहरी आर्थिक झटकों से अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

• The Reserve Bank of India actively manages forex reserves to ensure adequate liquidity and stability in the external sector.

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बाह्य क्षेत्र में पर्याप्त तरलता एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का सक्रिय प्रबंधन करता है।

Ques: Which committee of HDFC Bank is handling the process of CEO reappointment?

प्रश्न: HDFC बैंक में CEO की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया किस समिति द्वारा संचालित की जा रही है?

A) Audit Committee / ऑडिट समिति

B) Risk Management Committee / जोखिम प्रबंधन समिति

C) Governance, Nomination and Remuneration Committee (GNRC) / गवर्नेंस, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी (GNRC)

D) Credit Committee / ऋण समिति

E) Stakeholders Committee / हितधारक समिति

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• HDFC Bank's board is currently reviewing the reappointment of its Managing Director & Chief Executive Officer, Sashidhar Jagdishan.

• HDFC बैंक का बोर्ड वर्तमान में अपने प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(MD & CEO) शशिधर जगदीशन की पुनर्नियुक्ति पर विचार कर रहा है।

• The Governance, Nomination and Remuneration Committee (GNRC) is handling the process and is expected to complete its review soon.

• गवर्नेंस, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी (GNRC) इस प्रक्रिया का संचालन कर रही है और जल्द ही अपनी समीक्षा पूरी करने की उम्मीद है।

• Sashidhar Jagdishan's current three-year term is scheduled to end in October.

• शशिधर जगदीशन का वर्तमान तीन वर्षीय कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त होने वाला है।

• After the GNRC finalizes its recommendation, the proposal will be placed before the HDFC Bank Board for approval.

• GNRC की सिफारिश अंतिम होने के बाद प्रस्ताव स्वीकृति हेतु HDFC बैंक के बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

• Following board approval, the recommendation will be sent to the Reserve Bank of India (RBI) for final approval.

• बोर्ड की मंजूरी के बाद सिफारिश अंतिम स्वीकृति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भेजी जाएगी।

HDFC Bank | एचडीएफसी बैंक

• Established: 1994.
• स्थापना: 1994।
• Headquarters: Mumbai, Maharashtra.
• मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र।
• MD & CEO: Sashidhar Jagdishan.
• एमडी एवं सीईओ: शशिधर जगदीशन।
• Tagline: We Understand Your World.
• टैगलाइन: We Understand Your World.

Ques: What was the value of the Reserve Bank of India's Financial Inclusion (FI) Index for March 2026?

प्रश्न: मार्च 2026 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के वित्तीय समावेशन (FI) सूचकांक **का मान कितना रहा?**

A) 65.0
B) 67.0
C) 68.5
D) 70.0
E) 72.0

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) announced that the Financial Inclusion (FI) Index increased by 4.48% during FY 2025–26, reaching 70.0 in March 2026, compared to 67.0 in March 2025.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान वित्तीय समावेशन (FI) सूचकांक में 4.48% की वृद्धि हुई और मार्च 2026 में इसका मान 70.0 रहा, जबकि मार्च 2025 में यह 67.0 था।
• The FI Index is a composite index developed by the RBI to measure the level of financial inclusion in India.
• FI सूचकांक भारत में वित्तीय समावेशन के स्तर को मापने के लिए RBI द्वारा विकसित एक समग्र (Composite) सूचकांक है।
• The index ranges from 0 (Complete Financial Exclusion) to 100 (Complete Financial Inclusion) and has no base year.
• इस सूचकांक का मान 0 (पूर्ण वित्तीय बहिष्करण) से 100 (पूर्ण वित्तीय समावेशन) तक होता है तथा इसका कोई आधार वर्ष नहीं है।
• The RBI publishes the FI Index annually. The first FI Index was published in August 2021 for the financial year ending March 2021.
• RBI इस सूचकांक को प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है। पहला FI सूचकांक अगस्त 2021 में मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• The RBI FI Index is based on three dimensions.
• RBI FI सूचकांक तीन आयामों पर आधारित है।
• Access – 35%.

• पहुँच (Access) – 35%।
• Usage – 45%.
• उपयोग (Usage) – 45%।
• Quality – 20%.
• गुणवत्ता (Quality) – 20%।

Ques: The Government has revived the proposal to merge NaBFID with which institution?
प्रश्न: सरकार ने NaBFID के विलय का प्रस्ताव किस संस्था के साथ पुनः शुरू किया है?

A) SIDBI / भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
B) EXIM Bank / भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक)
C) IIFCL / इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
D) NABARD / राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
E) NHB / राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Central Government has revived the proposal to merge the National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) with the India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL).
• केंद्र सरकार ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) के विलय के प्रस्ताव को फिर से शुरू किया है।
• The proposed merger could create one of India's largest infrastructure financing institutions with a combined loan book of nearly ₹1.85 lakh crore.
• प्रस्तावित विलय से लगभग ₹1.85 लाख करोड़ के संयुक्त ऋण पोर्टफोलियो वाली भारत की सबसे बड़ी अवसंरचना वित्तपोषण संस्थाओं में से एक का गठन हो सकता है।
• The objective is to strengthen infrastructure financing, enhance lending

capacity and mobilise long-term domestic and international capital.

• इसका उद्देश्य अवसंरचना वित्तपोषण को मजबूत करना, ऋण देने की क्षमता बढ़ाना तथा दीर्घकालिक घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय पूंजी जुटाना है।

• The merger is expected to improve institutional efficiency and support India's expanding infrastructure development requirements.

• इस विलय से संस्थागत दक्षता बढ़ने तथा भारत की बढ़ती अवसंरचना विकास आवश्यकताओं को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

• The proposal was first considered several years ago and has now been revived by the Government.

• इस प्रस्ताव पर पहली बार कई वर्ष पहले विचार किया गया था, जिसे अब सरकार ने पुनः सक्रिय किया है।

NaBFID & IIFCL | NaBFID एवं IIFCL

National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID)

• Established: 2021.
• स्थापना: 2021।
• Type: Development Finance Institution (DFI).
• प्रकार: विकास वित्त संस्थान (DFI)।
• Purpose: Long-term Infrastructure Financing.
• उद्देश्य: दीर्घकालिक अवसंरचना वित्तपोषण।
• Headquarters: Mumbai, Maharashtra.
• मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र।

India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL)

• Established: 2006.
• स्थापना: 2006।
• Type: Government-Owned Infrastructure Finance Company.
• प्रकार: सरकारी स्वामित्व वाली अवसंरचना वित्त कंपनी।
• Headquarters: New Delhi.
• मुख्यालय: नई दिल्ली।
• Administrative Ministry: Ministry of Finance.
• प्रशासनिक मंत्रालय: वित्त मंत्रालय।

Ques: IndusInd Bank has integrated with which organisation to enable seamless Provident Fund (PF) contribution payments through the EPFO portal?
प्रश्न: इंडसइंड बैंक ने EPFO पोर्टल के माध्यम से निर्बाध प्रोविडेंट फंड (PF) अंशदान भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए किस संगठन के साथ एकीकरण किया है?

A) National Pension System Trust (NPS Trust) / राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट

B) Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) / कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

C) Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) / पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA)

D) National Payments Corporation of India (NPCI) / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)

E) Employees' State Insurance Corporation (ESIC) / कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• IndusInd Bank has integrated with the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) under the Ministry of Labour & Employment.
• इंडसइंड बैंक ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ एकीकरण किया है।
• The integration enables employers and establishments to make Provident Fund (PF) contributions seamlessly through the EPFO portal.
• इस एकीकरण से नियोक्ता एवं संस्थान EPFO पोर्टल के माध्यम से प्रोविडेंट फंड (PF) का अंशदान आसानी से जमा कर सकेंगे।
• Customers can make PF payments through Corporate Internet Banking (Indus Direct) and the INDIE for Business (MSME) mobile banking platform.
• ग्राहक कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग (Indus Direct) तथा INDIE for Business (MSME) मोबाइल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से PF भुगतान कर सकते हैं।
• The initiative is aimed at making PF compliance faster, more efficient and

convenient for businesses.
• इस पहल का उद्देश्य व्यवसायों के लिए PF अनुपालन प्रक्रिया को अधिक तेज़, प्रभावी और सुविधाजनक बनाना है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• IndusInd Bank was founded in April 1994.
• इंडसइंड बैंक की स्थापना अप्रैल 1994 में हुई थी।
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra.
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र।
• Managing Director & CEO – Rajiv Anand.
• प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) – राजीव आनंद।
• Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) was established in 1952.
• कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की स्थापना 1952 में हुई थी।
• Headquarters of EPFO – New Delhi.
• EPFO का मुख्यालय – नई दिल्ली।

Ques: Which bank earned the highest income from insurance distribution and commission in FY26?
प्रश्न: FY26 में बीमा वितरण एवं कमीशन से सर्वाधिक आय किस बैंक ने अर्जित की?

A) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक

B) Axis Bank / एक्सिस बैंक

C) SBI / भारतीय स्टेट बैंक

D) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक

E) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Major public and private sector banks earned more than ₹20,000 crore

through insurance distribution, brokerage and commission income during FY26.

• प्रमुख सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों ने FY26 में बीमा वितरण, ब्रोकरेज एवं कमीशन से ₹20,000 करोड़ से अधिक की आय अर्जित की।

• Nearly 80% of the total income came from the four largest private sector banks.

• कुल आय का लगभग 80% योगदान चार सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों से आया।

• HDFC Bank topped the list with insurance distribution income of ₹6,927 crore.

• HDFC बैंक ₹6,927 करोड़ की बीमा वितरण आय के साथ शीर्ष पर रहा।

• ICICI Bank earned ₹4,068 crore, followed by Axis Bank with ₹3,700 crore.

• ICICI बैंक ने ₹4,068 करोड़ तथा Axis बैंक ने ₹3,700 करोड़ की आय अर्जित की।

• SBI earned ₹2,795 crore, while Kotak Mahindra Bank reported ₹1,075 crore from insurance distribution.

• SBI ने बीमा वितरण से ₹2,795 करोड़ तथा Kotak Mahindra Bank ने ₹1,075 करोड़ की आय अर्जित की।

• The rising contribution from bancassurance highlights the growing importance of non-interest income for banks.

• Bancassurance से बढ़ती आय बैंकिंग क्षेत्र में गैर-ब्याज आय (Non-Interest Income) के बढ़ते महत्व को दर्शाती है।

Bancassurance | बैंकएश्योरेंस

• Bancassurance is a partnership between a bank and an insurance company to sell insurance products through the bank's distribution network.

• Bancassurance बैंक और बीमा कंपनी के बीच साझेदारी है, जिसके माध्यम से बैंक अपने नेटवर्क द्वारा बीमा उत्पादों की बिक्री करता है।

Top Insurance Distribution Income in FY26 | FY26 में बीमा वितरण से सर्वाधिक आय

• HDFC Bank – ₹6,927 crore.

• HDFC बैंक – ₹6,927 करोड़।

• ICICI Bank – ₹4,068 crore.

• ICICI बैंक – ₹4,068 करोड़।
• Axis Bank – ₹3,700 crore.
• Axis बैंक – ₹3,700 करोड़।
• SBI – ₹2,795 crore.
• SBI – ₹2,795 करोड़।
• Kotak Mahindra Bank – ₹1,075 crore.
• Kotak महिंद्रा बैंक – ₹1,075 करोड़।

Ques: Which bank reported a higher Return on Assets (RoA) in Q1 FY27?
प्रश्न: Q1 FY27 में किस बैंक ने अधिक Return on Assets (RoA) दर्ज किया?

A) HDFC Bank / HDFC बैंक

B) ICICI Bank / ICICI बैंक

C) SBI / एसबीआई

D) Axis Bank / एक्सिस बैंक

E) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• ICICI Bank retained its edge over HDFC Bank on several key performance indicators during Q1 FY27.
• ICICI बैंक ने Q1 FY27 में कई प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर HDFC बैंक पर अपनी बढ़त बरकरार रखी।
• HDFC Bank reported a net profit of ₹19,060 crore in Q1 FY27, registering a 5% year-on-year growth.
• HDFC बैंक ने Q1 FY27 में ₹19,060 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक है।
• ICICI Bank reported a net profit of ₹14,804.5 crore, recording a stronger year-on-year growth of 15.9%.

• ICICI बैंक ने ₹14,804.5 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जिसमें 15.9% की वार्षिक वृद्धि हुई।
• ICICI Bank outperformed HDFC Bank in key profitability indicators such as Return on Assets (RoA) and Return on Equity (RoE).
• ICICI बैंक ने Return on Assets (RoA) और Return on Equity (RoE) जैसे प्रमुख लाभप्रदता संकेतकों में HDFC बैंक से बेहतर प्रदर्शन किया।
• ICICI Bank reported a Return on Assets (RoA) of 2.5%, compared with HDFC Bank's RoA of about 1.9%.
• ICICI बैंक का Return on Assets (RoA) 2.5% रहा, जबकि HDFC बैंक का RoA लगभग 1.9% था।
• ICICI Bank also reported a Return on Equity (RoE) of around 17%, whereas HDFC Bank's RoE stood at around 14%.
• ICICI बैंक का Return on Equity (RoE) लगभग 17% रहा, जबकि HDFC बैंक का RoE लगभग 14% था।
• While HDFC Bank remained ahead in terms of overall size and absolute net profit, ICICI Bank demonstrated stronger profitability and operational efficiency during the quarter.
• यद्यपि HDFC बैंक कुल आकार और शुद्ध लाभ के मामले में आगे रहा, लेकिन ICICI बैंक ने तिमाही के दौरान बेहतर लाभप्रदता और परिचालन दक्षता का प्रदर्शन किया।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• ICICI Bank was established in 1994.
• ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी।
• Headquarters of ICICI Bank – Mumbai, Maharashtra.
• ICICI बैंक का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र।
• MD & CEO of ICICI Bank – Sandeep Bakhshi.
• ICICI बैंक के MD एवं CEO – संदीप बख्शी।
• Tagline of ICICI Bank – "Hum Hai Na, Khayal Apka".
• ICICI बैंक का टैगलाइन – "Hum Hai Na, Khayal Apka"।
• HDFC Bank was established in 1994.
• HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी।
• Headquarters of HDFC Bank – Mumbai, Maharashtra.
• HDFC बैंक का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र।

• MD & CEO of HDFC Bank – Sashidhar Jagdishan.
• HDFC बैंक के MD एवं CEO – शशिधर जगदीशन।
• Tagline of HDFC Bank – "We Understand Your World".
• HDFC बैंक का टैगलाइन – "We Understand Your World"।

Ques: Which two companies recently received SEBI approval to launch their IPOs?
प्रश्न: हाल ही में किन दो कंपनियों को IPO लाने के लिए SEBI की मंजूरी प्राप्त हुई?

A) Tata Capital & NSE / टाटा कैपिटल एवं एनएसई

B) Hero FinCorp & boAt / हीरो फिनकॉर्प एवं बोट

C) Absolute Projects (India) Ltd & Jindal Supreme (India) Ltd / एब्सोल्यूट प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड एवं जिंदल सुप्रीम (इंडिया) लिमिटेड

D) NSDL & HDB Financial Services / एनएसडीएल एवं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज

E) OYO & Ather Energy / ओयो एवं एथर एनर्जी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Absolute Projects (India) Ltd and Jindal Supreme (India) Ltd have received SEBI's approval to launch their Initial Public Offerings (IPOs).
• Absolute Projects (India) Ltd और Jindal Supreme (India) Ltd को अपना Initial Public Offering (IPO) लाने के लिए SEBI की मंजूरी मिल गई है।
• Both companies had filed their Draft Red Herring Prospectus (DRHP) with SEBI between April and May 2026.
• दोनों कंपनियों ने अप्रैल और मई 2026 के बीच SEBI के पास अपना Draft Red Herring Prospectus (DRHP) दाखिल किया था।
• SEBI issued its observations on 17 July 2026.
• SEBI ने 17 जुलाई 2026 को अपनी टिप्पणियां (Observations) जारी कीं।
• In SEBI terminology, the issuance of observations is treated as regulatory

approval to proceed with the IPO process.

• SEBI की शब्दावली में Observations जारी होने का अर्थ IPO प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नियामकीय मंजूरी माना जाता है।

Ques: Which ministry released India's first trial Index of Services Production (ISP) covering 19 service sub-sectors?

प्रश्न: 19 सेवा उप-क्षेत्रों को शामिल करते हुए भारत का पहला ट्रायल इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन (ISP) किस मंत्रालय ने जारी किया?

A) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय

B) Ministry of Commerce & Industry / वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

C) Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) / सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

D) Ministry of Corporate Affairs / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

E) Ministry of Heavy Industries / भारी उद्योग मंत्रालय

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) released India's first trial Index of Services Production (ISP) covering 19 service sub-sectors.

• सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 19 सेवा उप-क्षेत्रों को शामिल करते हुए भारत का पहला ट्रायल इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन (ISP) जारी किया।

• The first trial ISP covers April 2026 and uses 2024–25 as the base year, representing about 60% of India's services industry.

• पहला ट्रायल ISP अप्रैल 2026 को कवर करता है तथा 2024–25 को आधार वर्ष मानता है। यह भारत के लगभग 60% सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

• In April 2026, 14 out of 19 service sub-sectors recorded double-digit growth compared to the same month of the previous year.

• अप्रैल 2026 में 19 में से 14 सेवा उप-क्षेत्रों ने पिछले वर्ष के समान महीने की तुलना में दो अंकों (Double-digit) की वृद्धि दर्ज की।

• According to the trial ISP, only railway and air transport recorded a decline during April 2026.

• ट्रायल ISP के अनुसार, केवल रेलवे और हवाई परिवहन क्षेत्र में अप्रैल 2026 के दौरान गिरावट दर्ज की गई।

• Among the best-performing sectors, Accommodation & Food Services recorded the highest growth of 37.2%, followed by Retail Trade (30.8%), Administrative & Support Services (28.7%), and Real Estate (27.7%).

• सर्वाधिक वृद्धि आवास एवं खाद्य सेवाओं (Accommodation & Food Services) में 37.2% रही, इसके बाद रिटेल ट्रेड (30.8%), प्रशासनिक एवं सहायता सेवाएँ (28.7%), तथा रियल एस्टेट (27.7%) का स्थान रहा।

About Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बारे में:

• Cabinet Minister – Rao Inderjit Singh (Independent Charge)

• कैबिनेट मंत्री – राव इंदरजीत सिंह (स्वतंत्र प्रभार)

• Headquarters – New Delhi

• मुख्यालय – नई दिल्ली

• Responsible for – Official Statistics, National Surveys, and Monitoring of Government Programmes

• उत्तरदायी – आधिकारिक सांख्यिकी, राष्ट्रीय सर्वेक्षण तथा सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी

Ques: Why did the RBI intervene in the foreign exchange market recently?
प्रश्न: RBI ने हाल ही में विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप क्यों किया?

A) To increase gold reserves / स्वर्ण भंडार बढ़ाने के लिए

B) To strengthen the rupee amid its sharp fall / रुपये को गिरावट से बचाने के लिए

C) To reduce bank lending / बैंक ऋण कम करने के लिए

D) To control stock market volatility / शेयर बाजार की अस्थिरता नियंत्रित करने के

लिए

E) To increase exports / निर्यात बढ़ाने के लिए

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Indian Rupee fell to a two-month low of 96.53 against the US Dollar during intraday trade.

• भारतीय रुपया इंट्राडे कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दो महीने के निचले स्तर 96.53 पर पहुंच गया।

• The rupee finally settled at 96.45 per US Dollar, down 17 paise from the previous closing level.

• रुपया अंततः 96.45 प्रति अमेरिकी डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से 17 पैसे कमजोर रहा।

• Rising crude oil prices and geopolitical uncertainties increased pressure on the domestic currency.

• कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने रुपये पर दबाव बनाया।

• To prevent excessive depreciation and volatility, RBI intervened in the foreign exchange market by selling US Dollars.

• रुपये में अत्यधिक गिरावट और अस्थिरता को रोकने के लिए RBI ने विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर बेचकर हस्तक्षेप किया।

• Brent crude oil briefly touched around $91 per barrel before easing later in the day.

• ब्रेंट क्रूड ऑयल दिन के दौरान लगभग 91 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, लेकिन बाद में इसमें नरमी आई।

Reserve Bank of India (RBI) | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

• Established: 1 April 1935.

• स्थापना: 1 अप्रैल 1935।

• Headquarters: Mumbai, Maharashtra.

• मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र।
• Governor: Sanjay Malhotra.
• गवर्नर: संजय मल्होत्रा।
• Nationalised: 1 January 1949.
• राष्ट्रीयकरण: 1 जनवरी 1949।

Ques: SEBI imposed a penalty of ₹1 crore on which depository for cybersecurity lapses related to a malware attack?
प्रश्न: SEBI ने मालवेयर हमले से संबंधित साइबर सुरक्षा चूक के लिए किस डिपॉजिटरी पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया?

A) NSDL / एनएसडीएल

B) CDSL / सीडीएसएल

C) MCX / एमसीएक्स

D) NSE Clearing / एनएसई क्लियरिंग

E) BSE Ltd / बीएसई लिमिटेड

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• SEBI imposed a penalty of ₹1 crore on Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for violations of its cybersecurity and cyber-resilience framework.
• SEBI ने Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) पर साइबर सुरक्षा एवं साइबर-रेज़िलिएंस ढांचे के उल्लंघन के लिए ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया।
• The action was taken in connection with a malware attack that disrupted CDSL's operations in November 2022.
• यह कार्रवाई नवंबर 2022 में हुए मालवेयर हमले से संबंधित है, जिसने CDSL के परिचालन को प्रभावित किया था।
• SEBI found that critical systems remained disrupted for nearly 46 hours and 54.5 hours, affecting securities market settlement activities.

• SEBI ने पाया कि महत्वपूर्ण सिस्टम लगभग 46 घंटे और 54.5 घंटे तक बाधित रहे, जिससे प्रतिभूति बाजार की सेटलमेंट गतिविधियां प्रभावित हुईं।
• The regulator stressed that strong cyber-resilience measures are essential for ensuring market stability and protecting investor confidence.
• नियामक ने बाजार की स्थिरता बनाए रखने और निवेशकों का विश्वास सुरक्षित रखने के लिए मजबूत साइबर-रेज़िलिएंस उपायों के महत्व पर जोर दिया।

SEBI (Securities and Exchange Board of India) | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

• Established in 1988 and granted statutory status in 1992.
• स्थापना 1988 में हुई तथा 1992 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
• Headquarters: Mumbai, Maharashtra.
• मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र।
• Chairman: Tuhin Kanta Pandey.
• अध्यक्ष: तुहिन कांत पांडे।

CDSL (Central Depository Services (India) Ltd.) | सीडीएसएल

• Established: 1999.
• स्थापना: 1999।
• Headquarters: Mumbai, Maharashtra.
• मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र।
• MD & CEO: Nehal Vora.
• एमडी एवं सीईओ: नेहल वोरा।

Ques: Which organization recently revised its Grey List and Black List, following which the Reserve Bank of India (RBI) issued updated compliance instructions to Regulated Entities (REs)?
प्रश्न: किस संगठन ने हाल ही में अपनी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में संशोधन किया, जिसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विनियमित संस्थाओं (REs) को अनुपालन संबंधी निर्देश जारी किए?

A) International Monetary Fund (IMF) / अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

B) Financial Action Task Force (FATF) / वित्तीय कार्रवाई कार्यबल

C) World Bank / विश्व बैंक

D) Bank for International Settlements (BIS) / बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स

E) Asian Development Bank (ADB) / एशियाई विकास बैंक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) informed all Regulated Entities (REs) about the latest revisions made by the Financial Action Task Force (FATF) to its monitoring lists.

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी विनियमित संस्थाओं (REs) को Financial Action Task Force (FATF) द्वारा अपनी निगरानी सूचियों में किए गए नवीनतम संशोधनों की जानकारी दी।

• As per the June 2026 FATF update, Algeria and Namibia were removed from the Grey List.

• जून 2026 FATF अपडेट के अनुसार अल्जीरिया और नामीबिया को ग्रे लिस्ट से हटाया गया।

• Bosnia and Herzegovina and Iraq were added to the Grey List.

• बोस्निया और हर्जेगोविना तथा इराक को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया।

• RBI directed all regulated entities to update their Anti-Money Laundering (AML) and Counter Financing of Terrorism (CFT) risk management measures in line with the revised FATF lists.

• RBI ने सभी विनियमित संस्थाओं को संशोधित FATF सूचियों के अनुसार अपने धन शोधन निरोधक (AML) तथा आतंकवाद वित्तपोषण निरोधक (CFT) जोखिम प्रबंधन उपायों को अद्यतन करने का निर्देश दिया।

• FATF maintains two important monitoring lists: the Grey List (Jurisdictions Under Increased Monitoring) and the Black List (High-Risk Jurisdictions Subject to a Call for Action).

• FATF दो महत्वपूर्ण निगरानी सूचियाँ बनाए रखता है—ग्रे लिस्ट (अधिक निगरानी

वाले क्षेत्राधिकार) तथा ब्लैक लिस्ट (उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार, जिन पर कार्रवाई का आह्वान किया जाता है)।

About Financial Action Task Force (FATF) | फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के बारे में:

• Established – 1989
• स्थापना – 1989
• Headquarters – Paris, France
• मुख्यालय – पेरिस, फ्रांस
• President – Giles Thomson
• अध्यक्ष – Giles Thomson
• Purpose – To combat money laundering, terrorist financing, and proliferation financing by setting global standards.
• उद्देश्य – धन शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण तथा विनाशकारी हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण से निपटने हेतु वैश्विक मानक निर्धारित करना।

Ques: By what percentage did Canara HSBC Life Insurance's net profit increase in Q1 FY27?
प्रश्न: Q1 FY27 में केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस का शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत बढ़ा?

A) 15.15%
B) 18.66%
C) 20.15%
D) 23.83%
E) 16.20%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Canara HSBC Life Insurance reported a 20.15% year-on-year increase in net profit to ₹28.14 crore during Q1 FY27.

• केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस का शुद्ध लाभ Q1 FY27 में 20.15% बढ़कर ₹28.14 करोड़ हो गया।
• Net premium income increased by 23.83% year-on-year to ₹2,047.5 crore.
• शुद्ध प्रीमियम आय 23.83% बढ़कर ₹2,047.5 करोड़ हो गई।
• Annualised Premium Equivalent (APE) grew by 18.66% to ₹585 crore.
• एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट (APE) 18.66% बढ़कर ₹585 करोड़ हो गया।
• Investment income registered a growth of 16.2% and reached ₹2,268.79 crore.
• निवेश आय 16.2% बढ़कर ₹2,268.79 करोड़ हो गई।
• Assets Under Management (AUM) expanded by 14% and crossed ₹49,683 crore.
• प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (AUM) 14% बढ़कर ₹49,683 करोड़ से अधिक हो गईं।

Canara HSBC Life Insurance | केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस

• Founded: 2007.
• स्थापना: 2007।
• Headquarters: Gurugram, Haryana.
• मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा।
• MD & CEO: Anuj Mathur
• एमडी एवं सीईओ: अनुज माथुर
• Type: Private Life Insurance Company.
• प्रकार: निजी जीवन बीमा कंपनी।

EXAM Genius

Ques: According to RBI data, India's outward FDI commitments in June 2026 declined to approximately how much?
प्रश्न: RBI के अनुसार, जून 2026 में भारत का बाह्य FDI (Outward FDI) लगभग कितना रहा?

A) $2 Billion / 2 बिलियन डॉलर

B) $3 Billion / 3 बिलियन डॉलर

C) $4.5 Billion / 4.5 बिलियन डॉलर

D) $5.74 Billion / 5.74 बिलियन डॉलर

E) $6 Billion / 6 बिलियन डॉलर

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• According to provisional data released by the RBI, India's outward Foreign Direct Investment (FDI) commitments declined by 47.9% year-on-year to approximately $3 billion in June 2026.

• RBI द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Outward FDI) सालाना आधार पर 47.9% घटकर लगभग 3 बिलियन डॉलर रह गया।

• India's outward FDI commitments stood at $5.74 billion in June 2025 and $4.5 billion in May 2026.

• भारत का बाह्य FDI जून 2025 में 5.74 बिलियन डॉलर तथा मई 2026 में 4.5 बिलियन डॉलर था।

• RBI classifies outward FDI into equity investments, debt (loans) and guarantees extended to overseas entities.

• RBI के अनुसार, बाह्य FDI में इक्विटी निवेश, ऋण (Loans) तथा विदेशी संस्थाओं को दी गई गारंटियां शामिल होती हैं।

• Equity commitments declined to $738 million, while debt commitments fell to around $470 million in June 2026.

• जून 2026 में इक्विटी प्रतिबद्धताएं घटकर 738 मिलियन डॉलर तथा ऋण प्रतिबद्धताएं लगभग 470 मिलियन डॉलर रह गईं।

• Outward FDI reflects investments made by Indian companies and entities in overseas businesses and projects.

• Outward FDI भारतीय कंपनियों एवं संस्थाओं द्वारा विदेशों में किए जाने वाले निवेश को दर्शाता है।

Ques: How much fraud was reported by banks and financial institutions in India during the last five financial years?

प्रश्न: भारत में बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में कितनी धोखाधड़ी दर्ज की गई?

A) ₹75,000 Crore / ₹75,000 करोड़

B) ₹1 Lakh Crore / ₹1 लाख करोड़

C) ₹1.42 Lakh Crore / ₹1.42 लाख करोड़

D) ₹2 Lakh Crore / ₹2 लाख करोड़

E) ₹2.5 Lakh Crore / ₹2.5 लाख करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Banks and financial institutions in India reported frauds worth ₹1.42 lakh crore during the last five financial years.

• भारत में बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों ने पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में ₹1.42 लाख करोड़ की धोखाधड़ी दर्ज की।

• According to RBI data, recoveries worth ₹6,389 crore were made from fraud accounts during the same period.

• RBI के अनुसार, इसी अवधि में धोखाधड़ी वाले खातों से ₹6,389 करोड़ की वसूली की गई।

• Public Sector Banks (PSBs) recovered ₹52,360 crore from wilful defaulters as of 31 March 2026.

• 31 मार्च 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने विलफुल डिफॉल्टर्स (जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों) से ₹52,360 करोड़ की वसूली की।

• The Government informed Parliament that recovery from fraud accounts is a continuous process involving legal and regulatory measures.

• सरकार ने संसद में बताया कि धोखाधड़ी वाले खातों से वसूली एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें कानूनी एवं नियामकीय उपाय अपनाए जाते हैं।

• RBI and banks continue to strengthen fraud detection, monitoring and recovery mechanisms to safeguard the banking system.

• RBI और बैंक बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा के लिए धोखाधड़ी की पहचान, निगरानी और

वसूली तंत्र को लगातार मजबूत कर रहे हैं।

Ques: From which date has SEBI directed depositories to implement the new share buyback framework?
प्रश्न: सेबी ने डिपॉजिटरीज़ को नया शेयर बायबैक ढांचा किस तिथि से लागू करने का निर्देश दिया है?

A) July 1, 2026 / 1 जुलाई 2026

B) August 1, 2026 / 1 अगस्त 2026

C) September 1, 2026 / 1 सितंबर 2026

D) October 1, 2026 / 1 अक्टूबर 2026

E) January 1, 2027 / 1 जनवरी 2027

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• SEBI has directed depositories to put in place the required operational framework and system enhancements by 1 August 2026 for implementing the new share buyback mechanism.

• सेबी ने डिपॉजिटरीज़ को 1 अगस्त 2026 तक नया शेयर बायबैक ढांचा लागू करने हेतु आवश्यक परिचालन व्यवस्था एवं सिस्टम अपग्रेड तैयार करने का निर्देश दिया है।

• Under the new framework, the shareholding of promoters and promoter group entities will be frozen at the ISIN level during the buyback process.

• नई व्यवस्था के तहत शेयर बायबैक के दौरान प्रमोटर एवं प्रमोटर समूह की शेयरधारिता को ISIN स्तर पर फ्रीज किया जाएगा।

• Depositories will issue operational guidelines covering the freeze mechanism, promoter participation through the tender offer route, and the treatment of existing encumbrances on shares.

• डिपॉजिटरीज़ फ्रीज व्यवस्था, टेंडर ऑफर मार्ग से प्रमोटरों की भागीदारी, तथा शेयरों पर मौजूदा भार (Encumbrances) के प्रबंधन से संबंधित परिचालन दिशा-निर्देश जारी

करेंगी।
• The new framework is aimed at enhancing transparency, regulatory compliance and investor protection during the share buyback process.
• इस नई व्यवस्था का उद्देश्य शेयर बायबैक प्रक्रिया में पारदर्शिता, नियामकीय अनुपालन तथा निवेशक संरक्षण को मजबूत करना है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• Securities and Exchange Board of India (SEBI) was established in 1988 and received statutory status in 1992.
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की स्थापना 1988 में हुई तथा इसे 1992 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra.
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र।
• Chairman – Tuhin Kanta Pandey.
• अध्यक्ष – तुहिन कांत पांडेय।
• ISIN (International Securities Identification Number) is a unique identification code used to identify securities such as shares and bonds.
• ISIN (International Securities Identification Number) प्रतिभूतियों (जैसे शेयर एवं बॉन्ड) की पहचान के लिए प्रयुक्त एक विशिष्ट पहचान संख्या है।

Ques: According to the World Bank Country Income Classification (FY2027), India is classified under which income category?
प्रश्न: विश्व बैंक देश आय वर्गीकरण (FY2027) के अनुसार, भारत किस आय वर्ग में शामिल है?

A) Low-Income Economy / निम्न-आय अर्थव्यवस्था

B) Lower-Middle-Income Economy / निम्न-मध्यम-आय अर्थव्यवस्था

C) Upper-Middle-Income Economy / उच्च-मध्यम-आय अर्थव्यवस्था

D) High-Income Economy / उच्च-आय अर्थव्यवस्था

E) Developed Economy / विकसित अर्थव्यवस्था

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• According to the World Bank Country Income Classification (FY2027), India continues to be classified as a Lower-Middle-Income Economy.
• विश्व बैंक देश आय वर्गीकरण (FY2027) के अनुसार, भारत अभी भी निम्न-मध्यम-आय (Lower-Middle-Income) अर्थव्यवस्था की श्रेणी में बना हुआ है।
• India's Gross National Income (GNI) per capita, calculated using the Atlas Method, stood at US$2,760 in 2025.
• Atlas Method के अनुसार 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI per capita) US$2,760 रही।
• India has remained in the Lower-Middle-Income category since 2009.
• भारत 2009 से लगातार निम्न-मध्यम-आय श्रेणी में बना हुआ है।
• The World Bank uses Gross National Income (GNI) per capita based on the Atlas Method to classify countries into different income groups.
• विश्व बैंक देशों को विभिन्न आय वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए Atlas Method पर आधारित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI per capita) का उपयोग करता है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• FY2027 World Bank Income Classification:
• FY2027 विश्व बैंक आय वर्गीकरण:
• Low-Income Economies: US$1,175 or less.
• निम्न-आय अर्थव्यवस्था: US$1,175 या उससे कम।
• Lower-Middle-Income Economies: US$1,176 – US$4,635.
• निम्न-मध्यम-आय अर्थव्यवस्था: US$1,176 – US$4,635।
• Upper-Middle-Income Economies: US$4,636 – US$14,375.
• उच्च-मध्यम-आय अर्थव्यवस्था: US$4,636 – US$14,375।
• High-Income Economies: Above US$14,375.
• उच्च-आय अर्थव्यवस्था: US$14,375 से अधिक।

Ques: How much cumulative FDI did India receive in Single-Brand Retail Trading (SBRT) between FY22 and FY26?
प्रश्न: FY22 से FY26 के बीच भारत को सिंगल-ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग (SBRT) में कितना संचयी FDI प्राप्त हुआ?

A) $500 Million / $500 मिलियन

B) $1.0 Billion / $1.0 बिलियन

C) $1.52 Billion / $1.52 बिलियन

D) $2.5 Billion / $2.5 बिलियन

E) $3.0 Billion / $3.0 बिलियन

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• India received cumulative Foreign Direct Investment (FDI) of $1.52 billion in Single-Brand Retail Trading (SBRT) between FY22 and FY26.

• भारत को FY22 से FY26 के बीच सिंगल-ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग (SBRT) में कुल $1.52 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ।

• Annual FDI inflows in SBRT declined from $486.66 million in FY22 to $179.25 million in FY26.

• SBRT क्षेत्र में वार्षिक FDI प्रवाह FY22 के $486.66 मिलियन से घटकर FY26 में $179.25 मिलियन रह गया।

• During the same period, Multi-Brand Retail Trading (MBRT) received only $34.38 million in FDI.

• इसी अवधि में मल्टी-ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग (MBRT) को केवल $34.38 मिलियन का FDI प्राप्त हुआ।

• Under India's FDI policy, 100% FDI is permitted in Single-Brand Retail Trading through the automatic route, subject to local sourcing norms.

• भारत की FDI नीति के अनुसार, स्थानीय सोर्सिंग शर्तों के अधीन सिंगल-ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से 100% FDI की अनुमति है।

• The policy aims to attract global investment, improve retail infrastructure and promote domestic manufacturing through local sourcing requirements.

EXAM Genius

• इस नीति का उद्देश्य वैश्विक निवेश आकर्षित करना, खुदरा अवसंरचना को मजबूत करना तथा स्थानीय सोर्सिंग के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

Ques: Under the revised Portfolio Investment Scheme (PIS), the investment limit for an individual PROI has been increased to?
प्रश्न: संशोधित Portfolio Investment Scheme (PIS) के तहत एक व्यक्तिगत PROI की निवेश सीमा कितनी कर दी गई है?

A) 5%
B) 8%
C) 10%
D) 15%
E) 24%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has released draft rules to simplify India's foreign investment regulations and invited public comments until 31 August.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत के विदेशी निवेश नियमों को सरल बनाने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं तथा 31 अगस्त तक सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए हैं।
• The draft aims to reduce the compliance burden and align the regulatory framework with the Government of India's FDI policy.
• मसौदे का उद्देश्य अनुपालन बोझ कम करना तथा नियामकीय ढांचे को भारत सरकार की FDI नीति के अनुरूप बनाना है।
• It proposes a clear separation between FEMA operational provisions and FDI policy provisions, improving regulatory clarity and ease of doing business.
• इसमें FEMA के परिचालन प्रावधानों और FDI नीति प्रावधानों को अलग करने का प्रस्ताव है, जिससे नियामकीय स्पष्टता और कारोबार सुगमता बढ़ेगी।
• Under the revised Portfolio Investment Scheme (PIS), the investment limit for an individual Person Resident Outside India (PROI) has been increased from 5% to 10%.

• संशोधित Portfolio Investment Scheme (PIS) के तहत एक व्यक्तिगत Person Resident Outside India (PROI) की निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है।
• The aggregate investment limit for all PROIs under the PIS has also been increased from 10% to 24%.
• PIS के तहत सभी PROI के लिए कुल निवेश सीमा भी 10% से बढ़ाकर 24% कर दी गई है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• Reserve Bank of India (RBI) was established on 1 April 1935.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
• Headquarters of RBI – Mumbai, Maharashtra.
• RBI का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र।
• Governor of RBI – Sanjay Malhotra.
• RBI के गवर्नर – संजय मल्होत्रा।
• FEMA stands for Foreign Exchange Management Act, 1999.
• FEMA का पूर्ण रूप Foreign Exchange Management Act, 1999 (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999) है।

Ques: According to IEEFA, how much cumulative investment will India require to achieve its net-zero target by 2070?
प्रश्न: IEEFA के अनुसार, भारत को 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितने संचयी निवेश की आवश्यकता होगी?

A) $18 Trillion / $18 ट्रिलियन

B) $20 Trillion / $20 ट्रिलियन

C) $22.7 Trillion / $22.7 ट्रिलियन

D) $25 Trillion / $25 ट्रिलियन

E) $30 Trillion / $30 ट्रिलियन

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• According to the Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), India will require cumulative investments of about $22.7 trillion (₹2,167 lakh crore) by 2070 to achieve its net-zero emissions target.

• इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) के अनुसार, भारत को 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगभग $22.7 ट्रिलियन (₹2,167 लाख करोड़) के संचयी निवेश की आवश्यकता होगी।

• The report estimates that India could face a financing gap of around $6.5 trillion (₹620 lakh crore).

• रिपोर्ट के अनुसार भारत को लगभग $6.5 ट्रिलियन (₹620 लाख करोड़) के संभावित वित्तीय अंतर का सामना करना पड़ सकता है।

• IEEFA emphasized the need for stronger climate-transition disclosures by companies to attract long-term domestic and international investments.

• IEEFA ने दीर्घकालिक घरेलू एवं वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए कंपनियों द्वारा मजबूत क्लाइमेट-ट्रांजिशन डिस्क्लोजर की आवश्यकता पर जोर दिया।

• Improved transparency and climate-related financial disclosures are expected to strengthen investor confidence and support sustainable economic growth.

• बेहतर पारदर्शिता और जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा तथा सतत आर्थिक विकास को समर्थन मिलेगा।

• Achieving the net-zero target will require large-scale investments in renewable energy, clean technologies, energy efficiency and low-carbon infrastructure.

• नेट-ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता तथा निम्न-कार्बन अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) was established in 2011.

• इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) की स्थापना 2011 में हुई थी।

• Headquarters of IEEFA – Cleveland, Ohio, USA.

• IEEFA का मुख्यालय – क्लीवलैंड, ओहायो, अमेरिका।
• India has set a target of achieving Net Zero emissions by 2070.
• भारत ने वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
• India announced its Net Zero target at the COP26 Climate Summit held in Glasgow in 2021.
• भारत ने वर्ष 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में 2070 तक नेट-ज़ीरो का लक्ष्य घोषित किया था।

Ques: Bloomberg has integrated its Bloomberg Terminal with which platform to facilitate the first electronic trade in Indian Government Bonds (IGBs)?
प्रश्न: ब्लूमबर्ग ने भारतीय सरकारी बॉन्ड (IGBs) में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को सक्षम बनाने के लिए अपने Bloomberg Terminal को किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया है?

A) RBI e-Kuber / RBI ई-कुबेर

B) Negotiated Dealing System–Order Matching (NDS-OM) / नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम–ऑर्डर मैचिंग (NDS-OM)

C) National Stock Exchange (NSE) / नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)

D) BSE Bond Platform / बीएसई बॉन्ड प्लेटफॉर्म

E) CCIL TREPS Platform / CCIL TREPS प्लेटफॉर्म

Answer: Option B

EXAM Genius

Explanation | व्याख्या:

• Bloomberg has introduced a new electronic trading system that enables global investors to buy and sell Indian Government Bonds (IGBs) more efficiently, supporting greater access to India's bond market.
• ब्लूमबर्ग ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रणाली शुरू की है, जिससे वैश्विक निवेशक भारतीय सरकारी बॉन्ड (IGBs) की खरीद-बिक्री अधिक आसानी से कर सकेंगे और भारत के बॉन्ड बाज़ार तक उनकी पहुँच बढ़ेगी।

• Bloomberg facilitated the first electronic trade in Indian Government Bonds (IGBs) through the Bloomberg Terminal by integrating it with the Negotiated Dealing System–Order Matching (NDS-OM) platform.

• ब्लूमबर्ग ने Bloomberg Terminal को Negotiated Dealing System–Order Matching (NDS-OM) के साथ एकीकृत करके भारतीय सरकारी बॉन्ड (IGBs) की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को संभव बनाया।

• The Bloomberg Terminal is now directly connected to NDS-OM, providing an end-to-end electronic workflow for trading Government Securities (G-Secs).

• Bloomberg Terminal अब सीधे NDS-OM से जुड़ गया है, जिससे सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के व्यापार के लिए एंड-टू-एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ़्लो उपलब्ध हो गया है।

• NDS-OM is operated by Clearcorp Dealing Systems (India) Ltd.

• NDS-OM का संचालन Clearcorp Dealing Systems (India) Ltd. द्वारा किया जाता है।

About Negotiated Dealing System–Order Matching (NDS-OM) :

- Launched in : 2005
- Launched by : Reserve Bank of India (RBI)
- Operated by : Clearcorp Dealing Systems (India) Ltd.,
- Tradable Instruments : Central Government Securities (G-Secs), State Development Loans (SDLs), and Treasury Bills (T-Bills)
- Trade Settlement under NDS-OM follows the T+1 settlement cycle

---

Ques: According to ICRA, what is the projected GDP growth rate for India in Q1 FY2027?

प्रश्न: ICRA के अनुसार, Q1 FY2027 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी है?

A) 5.8–6.0%
B) 6.0–6.2%
C) 6.4–6.6%
D) 6.8–7.0%
E) 7.2–7.4%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• ICRA has projected India's GDP growth for Q1 FY2027 at 6.4–6.6%.
• ICRA ने Q1 FY2027 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.4–6.6% रहने का अनुमान लगाया है।
• The projected growth is lower than the 7.7% GDP growth recorded in the previous quarter.
• यह अनुमान पिछली तिमाही में दर्ज 7.7% GDP वृद्धि दर से कम है।
• The slowdown is mainly attributed to higher energy and input costs.
• इस धीमी वृद्धि का मुख्य कारण ऊर्जा एवं इनपुट लागत में वृद्धि है।
• Rising costs have reduced corporate profit margins.
• बढ़ती लागत के कारण कॉरपोरेट लाभ मार्जिन पर दबाव पड़ा है।
• Higher input costs are expected to weigh on value-added growth across several sectors of the economy.
• बढ़ी हुई लागत के कारण अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में वैल्यू-एडेड ग्रोथ प्रभावित होने की संभावना है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• ICRA Limited was established in 1991.
• ICRA लिमिटेड की स्थापना 1991 में हुई थी।
• Headquarters – Gurugram, Haryana.
• मुख्यालय – गुरुग्राम, हरियाणा।
• Full Form – Investment Information and Credit Rating Agency.
• पूरा नाम – Investment Information and Credit Rating Agency।
• Parent Company (Major Shareholder) – Moody's Corporation.
• प्रमुख हिस्सेदार (Parent Company) – Moody's Corporation।

Ques: According to RBI data, what was the net dollar sale by the RBI in the forex market during May 2026?
प्रश्न: RBI के अनुसार, मई 2026 में विदेशी मुद्रा (Forex) बाजार में RBI की शुद्ध डॉलर

बिक्री कितनी रही?

A) US$1.8 Billion / US$1.8 बिलियन

B) US$6.1 Billion / US$6.1 बिलियन

C) US$8.9 Billion / US$8.9 बिलियन

D) US$22.2 Billion / US$22.2 बिलियन

E) US$28.3 Billion / US$28.3 बिलियन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• According to RBI data, the Reserve Bank of India remained a net seller in the foreign exchange market during May 2026, with net dollar sales declining to US$6.1 billion from US$8.9 billion in April.

• RBI के अनुसार, मई 2026 में भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा (Forex) बाजार में शुद्ध विक्रेता (Net Seller) बना रहा, जबकि उसकी शुद्ध डॉलर बिक्री अप्रैल के US$8.9 बिलियन से घटकर US$6.1 बिलियन रह गई।

• Outstanding net forward sales increased to US$106.7 billion at the end of May, indicating the RBI's continued intervention in the foreign exchange market.

• मई 2026 के अंत तक बकाया शुद्ध फॉरवर्ड बिक्री बढ़कर US$106.7 बिलियन हो गई, जो विदेशी मुद्रा बाजार में RBI के लगातार हस्तक्षेप को दर्शाती है।

• During May 2026, RBI's gross dollar purchases increased to US$22.2 billion, while gross dollar sales rose to US$28.3 billion.

• मई 2026 के दौरान RBI की सकल डॉलर खरीद (Gross Purchases) बढ़कर US$22.2 बिलियन तथा सकल डॉलर बिक्री (Gross Sales) बढ़कर US$28.3 बिलियन रही।

• The RBI intervenes in the forex market to reduce excessive volatility in the rupee and ensure orderly market conditions.

• RBI विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने तथा बाजार में व्यवस्थित स्थिति बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करता है।

Ques: Under the new RBI prudential norms, within how many years must Banks, Small Finance Banks (SFBs), and NBFCs dispose of immovable assets acquired while resolving stressed loans (Specified Non-Financial Assets - SNFAs)?

प्रश्न: RBI के नए प्रूडेंशियल मानदंडों के अनुसार, तनावग्रस्त ऋणों (Specified Non-Financial Assets - SNFAs) के समाधान के दौरान प्राप्त अचल संपत्तियों का निपटान बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFBs) और NBFCs को अधिकतम कितने वर्षों के भीतर करना होगा?

A) 3 Years / 3 वर्ष

B) 5 Years / 5 वर्ष

C) 7 Years / 7 वर्ष

D) 10 Years / 10 वर्ष

E) 12 Years / 12 वर्ष

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has issued final prudential norms for Banks, Small Finance Banks (SFBs), and Non-Banking Financial Companies (NBFCs) regarding Specified Non-Financial Assets (SNFAs) acquired during the resolution of stressed loans or Non-Performing Assets (NPAs).

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने तनावग्रस्त ऋणों या गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के समाधान के दौरान प्राप्त Specified Non-Financial Assets (SNFAs) के संबंध में बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFBs) और NBFCs के लिए अंतिम प्रूडेंशियल मानदंड जारी किए हैं।

• Under the new framework, SNFAs cannot be sold back to the defaulting borrower or its related parties.

• नए ढांचे के तहत SNFA को डिफॉल्टर उधारकर्ता या उससे संबंधित पक्षों को दोबारा नहीं बेचा जा सकेगा।

• The Board-approved policy must prescribe limits on SNFAs, eligibility criteria, recovery efforts before acquisition, and a maximum disposal period of seven

years.

• बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में SNFA की सीमा, पात्रता मानदंड, अधिग्रहण से पूर्व वसूली प्रयास, तथा अधिकतम 7 वर्षों के भीतर निपटान का प्रावधान होना चाहिए।

• SNFAs must be disposed of as early as possible through public auctions in accordance with the principles of the SARFAESI Act, 2002, ensuring a transparent and competitive sale process.

• SNFA का निपटान यथाशीघ्र सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से SARFAESI Act, 2002 के सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, ताकि बिक्री प्रक्रिया पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी रहे।

• The initial valuation of an SNFA will be based on the lower of the Net Book Value (NBV) of the extinguished loan or the Distress Sale Value, determined by at least two independent external valuers.

• SNFA का प्रारंभिक मूल्यांकन समाप्त ऋण के Net Book Value (NBV) अथवा Distress Sale Value में से जो कम होगा, उसके आधार पर किया जाएगा। यह मूल्यांकन कम से कम दो स्वतंत्र बाहरी मूल्यांककों द्वारा किया जाएगा।

• The new RBI norms will come into effect from 1 October 2026, while legacy SNFAs held as of 30 September 2026 must comply with the new framework by 30 September 2027.

• RBI के नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे, जबकि 30 सितंबर 2026 तक धारित पुराने SNFAs को 30 सितंबर 2027 तक नए ढांचे के अनुरूप लाना होगा।

About SARFAESI Act, 2002 | SARFAESI अधिनियम, 2002 के बारे में:

• Full Form – Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

• पूर्ण नाम – प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

• Enacted – 2002

• अधिनियमित – 2002

• Purpose – To enable banks and financial institutions to recover defaulted loans without court intervention by enforcing secured assets.

• उद्देश्य – बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों के माध्यम से डिफॉल्ट ऋण की वसूली करने में सक्षम बनाना।

Ques: Roy Gori has been appointed as Senior Advisor by which global investment firm?
प्रश्न: रॉय गोरी को किस वैश्विक निवेश कंपनी ने Senior Advisor नियुक्त किया है?

A) Blackstone / ब्लैकस्टोन

B) KKR / केकेआर

C) Carlyle Group / कार्लाइल ग्रुप

D) Apollo Global Management / अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट

E) Brookfield / ब्रुकफील्ड

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Global investment firm KKR has appointed former Manulife President & CEO Roy Gori as its Senior Advisor.
• वैश्विक निवेश कंपनी KKR ने Manulife के पूर्व President एवं CEO रॉय गोरी को अपना Senior Advisor नियुक्त किया है।
• Roy Gori will advise KKR on strategic opportunities in insurance, wealth management, banking and financial services.
• रॉय गोरी KKR को बीमा, वेल्थ मैनेजमेंट, बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं से जुड़े रणनीतिक अवसरों पर सलाह देंगे।
• His role will focus on the Asia-Pacific region and other global markets.
• उनकी भूमिका एशिया-प्रशांत क्षेत्र तथा अन्य वैश्विक बाजारों पर केंद्रित होगी।
• He will support KKR's leadership in expansion, strategic partnerships and investment strategy.
• वे KKR के नेतृत्व को विस्तार, रणनीतिक साझेदारी तथा निवेश रणनीति के क्षेत्रों में मार्गदर्शन देंगे।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• KKR stands for Kohlberg Kravis Roberts & Co.
• KKR का पूर्ण नाम Kohlberg Kravis Roberts & Co. है।

• KKR was founded in 1976.
• KKR की स्थापना 1976 में हुई थी।
• Headquarters – New York, USA.
• मुख्यालय – न्यूयॉर्क, अमेरिका।
• Co-Founders – Henry Kravis, George R. Roberts and Jerome Kohlberg Jr.
• सह-संस्थापक – Henry Kravis, George R. Roberts एवं Jerome Kohlberg Jr.

Ques: Which institution publishes the Financial Stability Report (FSR) that provides a bi-annual assessment of India's financial system?
प्रश्न: भारत की वित्तीय प्रणाली का अर्धवार्षिक (Bi-annual) आकलन प्रस्तुत करने वाली Financial Stability Report (FSR) किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है?

A) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

B) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय

C) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक

D) National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) / नाबार्ड

E) Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) / भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Financial Stability Report (FSR) – June 2026 was published by the Reserve Bank of India (RBI), providing an overall assessment of the country's financial system.
• Financial Stability Report (FSR) – जून 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रकाशित किया, जिसमें देश की वित्तीय प्रणाली का समग्र आकलन प्रस्तुत किया गया है।
• The report is published twice a year (bi-annually) and reviews the condition of banks, NBFCs, insurance companies, mutual funds, and other financial

institutions.

• यह रिपोर्ट वर्ष में दो बार (अर्धवार्षिक) प्रकाशित होती है तथा बैंकों, NBFCs, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंडों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की स्थिति का आकलन करती है।

• The report highlights that geopolitical fragmentation and the rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) are the two major forces reshaping the global economy and financial system.

• रिपोर्ट के अनुसार भू-राजनीतिक विखंडन (Geopolitical Fragmentation) तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की तीव्र प्रगति वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं।

• The Gross Non-Performing Asset (GNPA) ratio is projected to increase slightly from 1.8% in March 2026 to 1.9% by March 2028 under the baseline scenario.

• सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात के मार्च 2026 के 1.8% से बढ़कर मार्च 2028 तक 1.9% होने का अनुमान है।

• Under adverse stress scenarios, the GNPA could rise to 3.8%–4.1%, indicating that the Indian banking system remains resilient even under severe stress conditions.

• प्रतिकूल परिस्थितियों (Adverse Scenarios) में GNPA 3.8%–4.1% तक बढ़ सकता है, फिर भी भारतीय बैंकिंग प्रणाली गंभीर तनाव की स्थिति में भी मजबूत (Resilient) बनी रहने का संकेत देती है।

Key Takeaways from RBI Financial Stability Report June 2026:

- Scheduled Commercial Bank - Credit Growth 14.5%
- Gross NPA Ratio - 1.8% (lowest in decades)
- Profit After Tax - ₹4.05 lakh crore
- Liquidity Coverage Ratio (LCR) - 124.2%
- Net Stable Funding Ratio (NSFR) - 122.1%
- Inflation Forecast - 5.1% Fastest
- Growing Retail Segment - Gold Loans

Macroeconomic Indicators & Projections :

- Real GDP Growth - 7.7%
- MPC GDP Projection - 6.6%
- Headline Inflation (Apr 2026) - 3.5%

- Headline Inflation (May 2026) - 3.9%
- MPC Inflation Projection - 4.6% – 5.1%

Scheduled Commercial Banks (SCBs) :

- CRAR (Capital Adequacy) - 17.7%
- CET 1 Ratio - 15.3%
- Liquidity Coverage Ratio - 124.2%
- Gross NPA (GNPA) - 1.8%
- Net NPA (NNPA) - 0.4%
- Provisioning Coverage Ratio - 75.6%
- Slippage Ratio - 1.2%
- Credit Growth - 14.5%
- Profit After Tax (PAT) Growth - 7.2%
- Net Interest Income Growth - 4.0%

About Financial Stability Report (FSR) | फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (FSR) के बारे में:

• Published By – Reserve Bank of India (RBI)
• प्रकाशितकर्ता – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
• Frequency – Bi-annual (Twice a Year)
• आवृत्ति – अर्धवार्षिक (वर्ष में दो बार)
• Purpose – To assess risks to India's financial system and evaluate the resilience of financial institutions.
• उद्देश्य – भारत की वित्तीय प्रणाली के जोखिमों का आकलन करना तथा वित्तीय संस्थानों की मजबूती (Resilience) का मूल्यांकन करना।

Ques: According to economists' projections, India's net FDI inflows may reach what level in FY2027?
प्रश्न: अर्थशास्त्रियों के अनुमान के अनुसार, FY2027 में भारत का शुद्ध FDI प्रवाह कितने स्तर तक पहुँच सकता है?

A) US$6.9 Billion / US$6.9 बिलियन

B) US$10 Billion / US$10 बिलियन

C) US$12 Billion / US$12 बिलियन

D) US$15 Billion / US$15 बिलियन

E) US$21.4 Billion / US$21.4 बिलियन

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Economists expect India's net Foreign Direct Investment (FDI) inflows to rise to around US$15 billion in FY2027.

• अर्थशास्त्रियों के अनुसार, भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) FY2027 में बढ़कर लगभग US$15 बिलियन हो सकता है।

• Net FDI inflows are projected to increase from US$6.9 billion in FY2026 to around US$15 billion in FY2027.

• FY2026 के US$6.9 बिलियन की तुलना में FY2027 में शुद्ध FDI प्रवाह लगभग US$15 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।

• During April–May FY2027, net FDI inflows surged 160% year-on-year to US$6.5 billion.

• FY2027 के अप्रैल–मई के दौरान शुद्ध FDI प्रवाह सालाना आधार पर 160% बढ़कर US$6.5 बिलियन हो गया।

• Higher gross FDI inflows and lower repatriation outflows are expected to support the rise in net FDI.

• सकल FDI प्रवाह में वृद्धि तथा पुनर्प्रेषण (Repatriation) में कमी के कारण शुद्ध FDI में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• FDI stands for Foreign Direct Investment.

• FDI का पूर्ण रूप Foreign Direct Investment है।

• FDI refers to investment made by a foreign entity in the business or assets of another country.

• FDI का अर्थ है किसी विदेशी संस्था द्वारा दूसरे देश के व्यवसाय या परिसंपत्तियों में किया गया निवेश।
• Gross FDI (April–May FY2027): US$21.4 Billion.
• सकल FDI (अप्रैल–मई FY2027): US$21.4 बिलियन।
• Net FDI (April–May FY2027): US$6.5 Billion.
• शुद्ध FDI (अप्रैल–मई FY2027): US$6.5 बिलियन।
• Repatriation (April–May FY2027): US$7.6 Billion.
• पुनर्प्रेषण (अप्रैल–मई FY2027): US$7.6 बिलियन।

Ques: Axis AMC recently acquired the Portfolio Management Services (PMS) business of which company?
प्रश्न: Axis AMC ने हाल ही में किस कंपनी के Portfolio Management Services (PMS) व्यवसाय का अधिग्रहण किया है?

A) ICICI Securities / आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़
B) HDFC Securities / एचडीएफसी सिक्योरिटीज़
C) Axis Securities / एक्सिस सिक्योरिटीज़
D) Kotak Securities / कोटक सिक्योरिटीज़
E) SBI Securities / एसबीआई सिक्योरिटीज़

Answer: Option C

EXAM Genius

Explanation | व्याख्या:

• Axis Asset Management Company (Axis AMC) has acquired the Portfolio Management Services (PMS) business of Axis Securities.
• एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी (Axis AMC) ने एक्सिस सिक्योरिटीज़ के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज़ (PMS) व्यवसाय का अधिग्रहण किया है।
• The acquisition strengthens Axis AMC's alternatives platform and expands its presence in the high-net-worth investor (HNI) segment.

• इस अधिग्रहण से Axis AMC के अल्टरनेट्स प्लेटफॉर्म को मजबूती मिलेगी तथा हाई नेट-वर्थ निवेशकों (HNI) के क्षेत्र में इसकी उपस्थिति बढ़ेगी।

• The acquired business will operate under the brand 'Alternates by Axis AMC' and brings more than 2,500 investors to the Axis AMC platform.

• अधिग्रहित व्यवसाय 'Alternates by Axis AMC' ब्रांड के तहत संचालित होगा तथा इससे 2,500 से अधिक निवेशक Axis AMC प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे।

• With this acquisition, Axis AMC's combined PMS Assets Under Management (AUM) will increase to around ₹15,000 crore, making it one of India's largest PMS acquisitions by investor count.

• इस अधिग्रहण के बाद Axis AMC की संयुक्त PMS प्रबंधित परिसंपत्तियाँ (AUM) लगभग ₹15,000 करोड़ हो जाएँगी, जिससे यह निवेशकों की संख्या के आधार पर भारत के सबसे बड़े PMS अधिग्रहणों में से एक बन जाएगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Axis Asset Management Company (Axis AMC) Parent Group – Axis Bank Group

• एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी (Axis AMC) का मूल समूह – एक्सिस बैंक समूह

• Headquarters – Mumbai, Maharashtra

• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

Ques: Which company has launched India's first UPI-enabled Meal Card?

प्रश्न: भारत का पहला UPI-सक्षम (UPI-enabled) मील कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया है?

A) Razorpay / रेज़रपे

B) Paytm / पेटीएम

C) EnKash / एनकैश

D) Pine Labs / पाइन लैब्स

E) MobiKwik / मोबिक्विक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• EnKash has launched India's first UPI-enabled Meal Card.

• EnKash ने भारत का पहला UPI-सक्षम (UPI-enabled) मील कार्ड लॉन्च किया है।

• The card enables employees to make payments directly from their meal benefit balance by scanning eligible UPI QR codes at food and grocery merchants.

• इस कार्ड के माध्यम से कर्मचारी फूड एवं ग्रॉसरी मर्चेंट्स पर पात्र UPI QR कोड स्कैन करके अपने मील बेनिफिट बैलेंस से सीधे भुगतान कर सकते हैं।

• It integrates employee meal benefits with the UPI ecosystem, eliminating the need for a separate physical meal card.

• यह कर्मचारी मील बेनिफिट्स को UPI इकोसिस्टम से जोड़ता है, जिससे अलग फिजिकल मील कार्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

• The initiative strengthens EnKash's Employee Benefits platform and promotes seamless, secure and cashless corporate meal payments across India.

• यह पहल EnKash के Employee Benefits प्लेटफ़ॉर्म को मजबूत बनाती है तथा पूरे भारत में सहज, सुरक्षित और कैशलेस कॉर्पोरेट मील भुगतान को बढ़ावा देती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• EnKash Founded – 2018

• EnKash की स्थापना – 2018

• Headquarters – Mumbai, Maharashtra

• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

• National Payments Corporation of India (NPCI) Established – 2008

• नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की स्थापना – 2008

• NPCI Headquarters – Mumbai, Maharashtra

• NPCI का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

• UPI Launched – 2016

• UPI की शुरुआत – 2016

• Regulator – Reserve Bank of India (RBI)

• नियामक – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

Ques: The National Stock Exchange (NSE) has launched Electronic Gold Receipts (EGRs), which are backed by gold stored in whose regulated vaults?
प्रश्न: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGRs) किसके द्वारा विनियमित (Regulated) वॉल्ट में सुरक्षित रखे गए सोने द्वारा समर्थित हैं?

A) RBI-regulated vaults / RBI द्वारा विनियमित वॉल्ट

B) SEBI-regulated vaults / SEBI द्वारा विनियमित वॉल्ट

C) NABARD-regulated vaults / NABARD द्वारा विनियमित वॉल्ट

D) PFRDA-regulated vaults / PFRDA द्वारा विनियमित वॉल्ट

E) SIDBI-regulated vaults / SIDBI द्वारा विनियमित वॉल्ट

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The National Stock Exchange (NSE) has introduced Electronic Gold Receipts (EGRs), enabling investors to buy and trade gold digitally without handling physical gold.

• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGRs) की शुरुआत की है, जिससे निवेशक भौतिक सोने के बिना डिजिटल रूप से सोना खरीद और ट्रेड कर सकते हैं।

• Each EGR is backed by physical gold stored in SEBI-regulated vaults, ensuring safety and transparency.

• प्रत्येक EGR SEBI द्वारा विनियमित वॉल्ट में सुरक्षित रखे गए वास्तविक सोने द्वारा समर्थित है, जिससे सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

• The EGRs are available in 999 (99.9% purity) and 995 (99.5% purity) standards.

• EGR 999 (99.9% शुद्धता) तथा 995 (99.5% शुद्धता) के दो मानकों में उपलब्ध हैं।

• Investors can choose from 10 mg, 100 mg, 1 g, 10 g, 100 g, and 1 kg denominations.

• निवेशक 10 मि.ग्रा., 100 मि.ग्रा., 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1 किलोग्राम के

विभिन्न मूल्यवर्गों में निवेश कर सकते हैं।

• EGRs are traded Monday to Friday, and the units are credited to the investor's demat account on a T+1 settlement basis.

• EGR का व्यापार सोमवार से शुक्रवार तक किया जा सकता है और ये T+1 सेटलमेंट के आधार पर अगले कार्यदिवस निवेशक के डीमैट खाते में जमा हो जाते हैं।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• National Stock Exchange (NSE) was established in 1992.
• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की स्थापना 1992 में हुई थी।
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra.
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र।
• Electronic Gold Receipt (EGR) is a SEBI-regulated instrument representing ownership of physical gold stored in accredited vaults.
• इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGR) एक SEBI-विनियमित साधन है, जो मान्यता प्राप्त वॉल्ट में सुरक्षित रखे गए भौतिक सोने के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है।
• SEBI became a statutory body in 1992.
• SEBI को 1992 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।

Ques: SBI Foundation is the Corporate Social Responsibility (CSR) arm of which bank?
प्रश्न: SBI Foundation किस बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) शाखा है?

A) Punjab National Bank (PNB) / पंजाब नेशनल बैंक

B) Bank of Baroda (BoB) / बैंक ऑफ बड़ौदा

C) State Bank of India (SBI) / भारतीय स्टेट बैंक

D) Canara Bank / केनरा बैंक

E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• SBI Foundation has launched the SBI Platinum Jubilee Asha Scholarship 2026 with a total budget outlay of ₹100 crore.

• SBI फाउंडेशन ने ₹100 करोड़ के बजट के साथ SBI Platinum Jubilee Asha Scholarship 2026 की शुरुआत की है।

• The scholarship programme aims to provide financial assistance to more than 25,000 meritorious students from economically disadvantaged families across India.

• इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 25,000 से अधिक मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

• Annual scholarships ranging from ₹15,000 to ₹15 lakh will be awarded depending on the category of the student.

• विद्यार्थियों की श्रेणी के अनुसार ₹15,000 से ₹15 लाख तक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

• The initiative is one of India's largest corporate scholarship programmes, promoting access to quality education.

• यह भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट छात्रवृत्ति कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• SBI Foundation Established – 2015

• SBI फाउंडेशन की स्थापना – 2015

• Headquarters – Mumbai, Maharashtra

• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

• SBI Foundation is the CSR arm of State Bank of India (SBI).

• SBI फाउंडेशन भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) शाखा है।

• State Bank of India Chairman – Challa Sreenivasulu Setty (C. S. Setty)

• भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष – चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी (सी. एस. शेट्टी)

• SBI Managing Directors (2026) – Ashwini Kumar Tewari, Rana Ashutosh Kumar Singh, Rama Mohan Rao Amara, Ravi Ranjan

• SBI के प्रबंध निदेशक (2026) – अश्विनी कुमार तिवारी, राणा आशुतोष कुमार सिंह,

रामा मोहन राव अमारा, रवि रंजन

Ques: Viyona Fintech has received BBPS approval to operate as which type of entity?
प्रश्न: Viyona Fintech को BBPS के तहत किस प्रकार की इकाई के रूप में कार्य करने की मंजूरी मिली है?

A) Bharat Bill Operating Bank / भारत बिल ऑपरेटिंग बैंक

B) Customer Operating Unit (COU) / कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट (COU)

C) Payment Aggregator / पेमेंट एग्रीगेटर

D) Payment Bank / पेमेंट बैंक

E) White Label ATM Operator / व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Viyona Fintech has received approval from the Bharat Bill Payment System (BBPS) to operate as a Customer Operating Unit (COU).

• Viyona Fintech को भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) के तहत Customer Operating Unit (COU) के रूप में कार्य करने की मंजूरी मिली है।

• The approval enables Viyona to provide BBPS-powered bill payment services across India.

• इस मंजूरी के बाद Viyona पूरे भारत में BBPS आधारित बिल भुगतान सेवाएँ प्रदान कर सकेगी।

• The services include electricity, water, gas, broadband, mobile recharge, DTH, insurance premiums, loan EMIs and education fees.

• इन सेवाओं में बिजली, पानी, गैस, ब्रॉडबैंड, मोबाइल रिचार्ज, DTH, बीमा प्रीमियम, लोन EMI तथा शिक्षा शुल्क का भुगतान शामिल है।

• The certification strengthens Viyona's fintech infrastructure and expands secure digital bill payment services nationwide.

• यह प्रमाणन Viyona के फिनटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा तथा देशभर में सुरक्षित डिजिटल बिल भुगतान सेवाओं का विस्तार करेगा।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• BBPS stands for Bharat Bill Payment System.
• BBPS का पूर्ण नाम भारत बिल भुगतान प्रणाली (Bharat Bill Payment System) है।
• Launched – 2017.
• शुरुआत – 2017।
• Operated by – NPCI Bharat BillPay Limited (NBBL).
• संचालन – NPCI Bharat BillPay Limited (NBBL) द्वारा।
• Regulated by – Reserve Bank of India (RBI).
• नियामक – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)।
• Purpose – An integrated platform for interoperable and secure bill payments across India.
• उद्देश्य – पूरे भारत में इंटरऑपरेबल एवं सुरक्षित बिल भुगतान के लिए एकीकृत मंच उपलब्ध कराना।

Ques: The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has invited applications under the 'On-Tap' registration system for appointing which entities?
प्रश्न: पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 'ऑन-टैप' पंजीकरण प्रणाली के तहत किन संस्थाओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं?

A) Pension Fund Managers / पेंशन फंड प्रबंधक

B) Insurance Brokers / बीमा ब्रोकर

C) Stock Exchanges / स्टॉक एक्सचेंज

D) Asset Reconstruction Companies / परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ

E) Credit Rating Agencies / क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• PFRDA has invited applications from companies to function as Pension Fund Managers (PFMs) under the National Pension System (NPS) and the Unified Pension Scheme (UPS).

• PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) तथा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के अंतर्गत पेंशन फंड प्रबंधक (PFM) के रूप में कार्य करने के लिए कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

• Pension Fund Managers invest and manage the contributions made by subscribers under pension schemes such as NPS and UPS.

• पेंशन फंड प्रबंधक NPS और UPS जैसी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अंशधारकों द्वारा जमा किए गए धन का निवेश एवं प्रबंधन करते हैं।

• Under the new 'On-Tap' Registration system, companies can submit applications at any time instead of waiting for a fixed registration window.

• नई 'ऑन-टैप' पंजीकरण प्रणाली के तहत कंपनियाँ किसी भी समय आवेदन कर सकती हैं, जबकि पहले आवेदन केवल निर्धारित अवधि में स्वीकार किए जाते थे।

• The previous On-Tap Registration window was opened in May 2022.

• इससे पहले ऑन-टैप पंजीकरण की व्यवस्था मई 2022 में शुरू की गई थी।

• To qualify, a company must have at least 5 years' experience in managing equity and debt funds, be engaged in financial services, be regulated by RBI, SEBI or IRDAI, maintain a minimum net worth of ₹50 crore during each of the previous five financial years, and have a minimum paid-up capital of ₹25 crore.

• पात्रता के लिए कंपनी के पास इक्विटी एवं डेट फंड प्रबंधन का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव, वित्तीय सेवाओं में कार्य, RBI, SEBI या IRDAI में से किसी एक द्वारा विनियमित होना, पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम ₹50 करोड़ की शुद्ध संपत्ति (Net Worth) तथा आवेदन की तिथि पर ₹25 करोड़ की न्यूनतम चुकता पूंजी (Paid-up Capital) होना आवश्यक है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) was established in 2003 and became a statutory body under the PFRDA Act, 2013.

• पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) की स्थापना 2003 में हुई

तथा PFRDA अधिनियम, 2013 के तहत इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।

• Headquarters – New Delhi.

• मुख्यालय – नई दिल्ली।

• National Pension System (NPS) is a voluntary, defined-contribution pension scheme regulated by PFRDA.

• राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है, जिसका विनियमन PFRDA करता है।

• Unified Pension Scheme (UPS) is an option available under the National Pension System (NPS) for eligible Central Government employees.

• यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत उपलब्ध एक विकल्प है।

Ques: What was the Central Government's debt-to-GDP ratio in Financial Year 2025–26?

प्रश्न: वित्त वर्ष 2025–26 में केंद्र सरकार का ऋण-से-जीडीपी (Debt-to-GDP) अनुपात कितना था?

A) 56.8%
B) 57.5%
C) 58.2%
D) 58.5%
E) 60.1%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Central Government's debt-to-GDP ratio declined slightly to 58.2% in Financial Year 2025–26, compared with 58.5% in Financial Year 2024–25.

• वित्त वर्ष 2025–26 में केंद्र सरकार का ऋण-से-जीडीपी (Debt-to-GDP) अनुपात घटकर 58.2% हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 में यह 58.5% था।

• The total Central Government debt stood at ₹201.17 lakh crore as of 31 March 2026.

EXAM Genius

• 31 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार का कुल ऋण ₹201.17 लाख करोड़ था।

• This information was provided by Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary in a written reply in the Rajya Sabha.

• यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से दी।

• The Debt-to-GDP Ratio compares the government's total debt with the size of the country's economy (GDP). A lower ratio generally indicates that debt is growing more slowly than the economy or that debt is being managed more efficiently.

• Debt-to-GDP Ratio सरकार के कुल ऋण की तुलना देश की अर्थव्यवस्था (GDP) के आकार से करता है। इस अनुपात में कमी सामान्यतः यह दर्शाती है कि ऋण की वृद्धि अर्थव्यवस्था की तुलना में धीमी है या सरकार अपने ऋण का बेहतर प्रबंधन कर रही है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• GDP stands for Gross Domestic Product.

• GDP का पूर्ण रूप Gross Domestic Product (सकल घरेलू उत्पाद) है।

• The Debt-to-GDP Ratio is a key indicator of a country's fiscal sustainability.

• Debt-to-GDP Ratio किसी देश की राजकोषीय स्थिरता (Fiscal Sustainability) का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

• A lower Debt-to-GDP Ratio generally reflects better debt management and stronger fiscal health.

• Debt-to-GDP Ratio में कमी सामान्यतः बेहतर ऋण प्रबंधन एवं मजबूत राजकोषीय स्थिति का संकेत मानी जाती है।

• Nominal GDP is commonly used while calculating the Debt-to-GDP Ratio.

• Debt-to-GDP Ratio की गणना में सामान्यतः नाममात्र GDP (Nominal GDP) का उपयोग किया जाता है।